

प्रेषक,
निधि मणि त्रिपाठी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 15 नवम्बर, 2010

विषय: राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रशासनिक, वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 18-3-2010 को सीएसएमसी की 82वीं बैठक में राजीव आवास योजनान्तर्गत मलिन/बायोमैट्रिक/जीआईएस सर्वे, जीआईएस एवं एमआईएस के एकीकरण तथा सिटी टैक्नीकल सेल, हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं मलिन बस्ती मुक्त करने की प्लानिंग करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के लिए ₹ 229.25 लाख संस्तुत किये गये हैं। उक्त संस्तुति के सापेक्ष व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(8)/PF-I/2009-829 दिनांक 31-3-2010 द्वारा ₹ 114.63 लाख अवमुक्त किये गये हैं।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि ₹ 114.63 लाख में से ₹ 45.48 लाख (₹ पैंतालिस लाख अड़तालिस हजार मात्र) धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. दिनांक 18-3-2010 को हुई सीएसएमसी की बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उक्त प्रयोजन पर ही व्यय की जायेगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का

अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

5. उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जाये।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2011 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
- 3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-001-निर्देशन तथा प्रशासन-08-परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारियों एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु के मानक मद '42 अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 590/XXVII(2)/2010, दिनांक- 04 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

सं0- 1896 (1)/IV(2)-शा0वि0-08, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव